सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज मैकेन्जीज एण्ड ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कर निर्धारण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) सरकार कब से इसकी जांच कर रही है;

(ग) उस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस मामले में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) निम्नलिखित निर्धारण पूरे हो चुके हैं :—

मैसर्स मैकेन्जीज लि०	कर निर्धारण वर्ष 1962–63
मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	कर निर्धारण वर्ष 1963–64

बाद के वर्षों के खातों की छानबीन की जा रही है।

(ख) इन मामलों के समूह के बारे में जांच 1966 के मध्य में शुरू हुई थी।

(ग) तथा (घ) जिन लेन-देनों की पड़ताल की जानी है वे संख्या में बहुत अधिक हैं। चूंकि जांच की समाप्ति साक्षियों के सहयोग पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें कुछ और समय लगेगा। निर्धारण के काम को शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

Accommodation for party leaders

5521. Shri S. K. Tapuriah: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the names of party leaders who have been allotted Government houses and flats;

(b) whether the rents are charged at commercial rates or at special rates; and

(c) the amount of rent outstanding at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1028/67].

नर्मदा सागर परियोजना

5522. श्री ब्रह्मानन्दजी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-रूस व्यापार करार के अन्तर्गत नर्मदा सागर योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से बातचीत करने के लिये वहां के मुख्य मन्त्री को रूस भेजा गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) उक्त कार्य के कब से आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) दोनों देशों द्वारा पृथक्-पृथक् कितनी राशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस परियोजना पर कार्य तब आरम्भ होगा जब यह कार्यान्विति के लिए स्वीकार हो जायेगी। मध्य प्रदेश सरकार से

पुनरीक्षित नर्मदा सागर बिजली परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Birlas Companies in New York and London

5524. Shri Bhogendra Jha: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Birlas have one Company in London and another in New York for the exclusive purpose of running the invoicing racket; and

(b) if so, the steps Government propose to take or have already taken in the matter?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The Government are aware that the Birla group has certain firms in London and New York but they have no information that these concerns are meant for the purpose of running an invoicing racket.

(b) Does not arise.

Dispute between O.N.G.C. and Gujarat Government re. price of Gas

5525. Shri R. K. Amin:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri M. Amersey:
Shri Ramachandra J. Amin:
Shri D. R. Parmar:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) when the dispute between the Gujarat Government and the Oil and Natural Gas Commission about the price of gas in Gujarat first arose;

(b) when this question was referred for arbitration to Dr. V. K. R. V. Rao, the then Member of the Planning Commission;

(c) the terms of reference to the arbitrator;

(d) how much more time would still be taken by the arbitrator before he gives his award;

(e) whether any time limit has been set for the award by the arbitrator considering that inordinate delay has already occurred resulting in non-utilisation of gas for the purpose of industrial development of Gujarat; and

(f) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) The dispute arose in 1963.

(b) In February, 1964.

(c) The terms of reference are,—

(i) the price that should be charged by the ONG Commission for the gas that may be supplied after taking into consideration the volume and pressure of gas supplied to any particular party and the distance to which it has to be carried; and

(ii) to indicate if the ONGC should offer any differential in rates in respect of gas supplied to:

(i) undertakings for the generation of power;

(ii) Fertiliser Plants;

(iii) State Projects;

(iv) Private Sector industries; and

(v) domestic fuel.

(d) to (f). The Arbitrator is expected to give his award by the end of August, 1967. The delay in giving the award, has not, however, resulted in the non-utilization of gas for industrial purposes.

गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़

5526. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० सूर्यप्रकाश पुरी :